साप्ताहिक
Live not just breaTHE

दि कार्मिक पोस्ट

MPHIN/2015/63220
MP/IDC1528/22-23

Global School Of Excellence, Obedullaganj

Earth provides enough to satisfy every man's needs, but not every

वर्ष : 8, अंक : 12 (प्रति बुधवार), इन्दौर, 9 नवंबर 2022 से 15 नवंबर 2022 पेज : 8 कीमत : 3 रुपये

कॉप-27- जलवायु परिवर्तन से बढ़ेंगी बीमारियां, हर साल 2.50 लाख अतिरिक्त मौतों के आसार

कॉप 27 जलवायु वार्ता

नई दिल्ली। कॉप 27 जलवायु वार्ता में विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने चेतावनी देते हुए कहा है कि जलवायु संकट से लोग बीमार हो रहे हैं और यह जीवन को खतरे में डाल रहा है। इन महत्वपूर्ण वार्ताओं में स्वास्थ्य चर्चा के केंद्र में होना चाहिए।

डब्ल्यूएचओ का मानना ??है कि सम्मेलन को जलवायु संकट से निपटने के लिए शमन, अनुकूलन, वित्तपोषण और सहयोग के चार प्रमुख लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ना चाहिए। कॉप 27 दुनिया के एक साथ आने और 1.5 डिग्री सेल्सियस पेरिस समझौते के लक्ष्य को जीवित रखने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है। हमारा ध्यान जलवायु संकट से स्वास्थ्य को होने वाले खतरे और चर्चा के केंद्र में कठोर जलवायु कार्रवाई से होने वाले स्वास्थ्य लाभ पर होगा। जलवायु परिवर्तन पहले से ही लोगों के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रहा है और जब तक तत्काल कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक यह तेजी से बढ़ता रहेगा।

डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक डॉ टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस ने कहा कि जलवायु परिवर्तन दुनिया भर में लाखों लोगों को बीमार या बीमारी के प्रति अधिक असरदार बना रहा है। चरम मौसम की घटनाओं की बढ़ती विनाशकारीता गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों को असमान रूप से प्रभावित करते हैं। यह महत्वपूर्ण है कि बातचीत के केंद्र में स्वास्थ्य को रखने के लिए नेता और निर्णय निर्माता कॉप 27 में एक साथ आएं। हमारा स्वास्थ्य हमारे आस-पास के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है, ये पारिस्थितिकी तंत्र अब वनों को काटे जाने, कृषि और भूमि उपयोग में बदलाव तथा तेजी से हो रहे शहरी विकास के चलते खतरे में हैं। जानवरों के आवासों में अतिक्रमण अब मनुष्यों के लिए हानिकारक विषाणुओं संक्रमण के अवसरों को बढ़ा रहा है। 2030 से 2050 के बीच, जलवायु परिवर्तन से कुपोषण, मलेरिया, डायरिया और गर्मी के तनाव से हर साल लगभग

250000 अतिरिक्त मौतें हो सकती हैं। स्वास्थ्य के लिए प्रत्यक्ष क्षति लागत (अर्थात, कृषि और पानी और स्वच्छता जैसे स्वास्थ्य-निर्धारण वाले क्षेत्रों की लागत को छोड़कर), 2030 तक प्रति वर्ष दो से चार बिलियन अमेरिकी डॉलर के बीच होने का अनुमान है। वैश्विक तापमान में वृद्धि जो पहले ही हो चुकी है, चरम मौसम की घटनाओं को जन्म दे रही है जो भीषण गर्मी और सूखा, विनाशकारी बाढ़ और तेजी से बढ़ते खतरनाक तूफान और उष्णकटिबंधीय तूफानों को दावत दे रही है। इन कारणों के जुड़ने का अर्थ है कि लोगों के स्वास्थ्य पर प्रभाव बढ़ रहा है और इसमें और तेजी आने के आसार हैं। डब्ल्यूएचओ सरकारों से जीवाश्म ईंधन से न्यायसंगत और तेजी से स्वच्छ ऊर्जा की ओर जाने का आह्वान कर रहा है। डीकार्बोनाइजेशन या कार्बन पर रोक लगाने के लिए किए गए वादों पर भी उत्साहजनक प्रगति हुई है। डब्ल्यूएचओ एक जीवाश्म ईंधन अप्रसार संधि के निर्माण का आह्वान कर रहा है जो कोयले और अन्य जीवाश्म ईंधन से होने वाले हानिकारक प्रभाव को समाप्त कर देगा। साथ ही यह जलवायु परिवर्तन को कम करने में सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक का प्रतिनिधित्व करेगा।

लोगों के स्वास्थ्य में सुधार एक ऐसी चीज है जिसमें सभी नागरिक योगदान कर सकते हैं, इसमें अधिक शहरी हरित स्थानों को बढ़ावा देकर, जो वायु प्रदूषण के खतरे को कम करते हुए जलवायु शमन और अनुकूलन की सुविधा प्रदान करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर सामुदायिक जुड़ाव और भागीदारी भोजन और स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए आवश्यक है। यह कमजोर समुदायों और छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (एसआईडीएस) के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है, जो चरम मौसम की घटनाओं का खामियाजा भुगत रहे हैं। अफ्रीका के ग्रेटर हॉर्न में 3.1 करोड़ लोग भीषण भूखमरी का सामना कर रहे हैं और 1.1 करोड़ बच्चे गंभीर कुपोषण का सामना कर रहे हैं क्योंकि यह क्षेत्र हाल के दशकों में सबसे भयंकर सूखे की मार झेल रहा है। जलवायु परिवर्तन का पहले से ही खाद्य सुरक्षा पर प्रभाव पड़ा है और अगर मौजूदा रुझान जारी रहे, तो यह और खराब होगा। डब्ल्यूएचओ सभी को इन मुद्दों पर अपने स्थानीय नेताओं के साथ काम करने और अपने समुदायों में कार्रवाई करने के लिए प्रोत्साहित करता है। डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि स्वास्थ्य को अब जलवायु नीति के केंद्र में रखना चाहिए और जलवायु परिवर्तन शमन नीतियों को बढ़ावा देना चाहिए जो एक साथ स्वास्थ्य को फायदा पहुंचाती हैं। स्वास्थ्य-केंद्रित जलवायु नीति एक ऐसे ग्रह को बनाने में मदद करेगी जिसमें स्वच्छ हवा, अधिक प्रचुर मात्रा में और सुरक्षित ताजे या मीठा पानी और भोजन, अधिक प्रभावी और निष्पक्ष स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रणालियां हों। स्वच्छ ऊर्जा में निवेश से स्वास्थ्य को फायदा मिलेगा जो उन निवेशों को दोगुना कर देगा। ऐसे जांचे हस्तक्षेप हैं जो छोटे समय में जलवायु प्रदूषकों के उत्सर्जन को कम करने में सक्षम हैं, उदाहरण के लिए वाहन उत्सर्जन के लिए उच्च मानकों को लागू करना, जिससे हर साल लगभग 24 लाख जीवन बचाए जा सकते हैं। बेहतर वायु गुणवत्ता के माध्यम से और बढ़ते तापमान को 2050 तक लगभग 0.5 डिग्री सेल्सियस तक कम किया जा सकता है। ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों की लागत पिछले कुछ वर्षों में काफी कम हो गई है और सौर ऊर्जा अब अधिकांश प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में कोयले या गैस से सस्ती है।

ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करने वाले पशुओं पर टैक्स, पर्यावरण के प्रति न्यूजीलैंड की नई पहल

नई दिल्ली जलवायु परिवर्तन में मवेशियों की हिस्सेदारी को कम करने के लिए न्यूजीलैंड ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन करने वाले पशुओं पर टैक्स लगाने की योजना बना रहा है। ऐसी पहल करने वाला वह दुनिया का पहला देश है। न्यूजीलैंड के कुछ किसान इसका विरोध कर रहे हैं, वहीं प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न को उम्मीद है कि इसके जरिये वर्ष 2030 तक मीथेन, नाइट्रस आक्साइड और कार्बन डाई-आक्साइड जैसी ग्रीनहाउस गैसों के उत्सर्जन को 10 प्रतिशत तक घटाने और 2050 तक राष्ट्रीय स्तर पर शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करना संभव होगा। दुनिया में पहली बार जलवायु परिवर्तन का खतरा कम करने की मुहिम में किसानों और पशुपालकों को हिस्सेदार बनाया जा रहा है। यह अन्य देशों के लिए प्रेरक है। न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में पशुओं का महत्वपूर्ण योगदान है। वहां पशुओं की संख्या मनुष्यों से कहीं अधिक है। 50 लाख की आबादी के मुकाबले वहां करीब एक करोड़ गाय और ढाई करोड़ भेड़ हैं। न्यूजीलैंड में कुल ग्रीनहाउस गैसों के आधे हिस्से के उत्सर्जन के लिए पशुओं के पाचन तंत्र को जिम्मेदार माना जाता है। उल्लेखनीय है कि मवेशियों के मूत्र से नाइट्रस आक्साइड और उनकी डकार से मीथेन गैस का उत्सर्जन होता है। सामान्यत: एक मवेशी के डकारने से साल भर में 80 से 120 किलो तक मीथेन गैस निकलती है। इस तरह करोड़ों पशुओं के होने से न्यूजीलैंड को बड़ी पर्यावरणीय कीमत चुकानी पड़ती है। सरकार का मानना है कि पशुओं पर लगाए जाने वाले इस कर से प्राप्त राजस्व का इस्तेमाल पशुओं की नई प्रजाति तैयार करने, अनुसंधान और जलवायु हितैषी किसानों को आर्थिक संबल प्रदान करना है।

देश में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहर है, इसके बाद अनेक राज्यों की राजधानियां भी प्रदूषण में एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं

नई दिल्ली। अपने देश में दिल्ली सर्वाधिक प्रदूषित शहर है। इसके बाद अनेक राज्यों की राजधानियां भी प्रदूषण में एक दूसरे को टक्कर दे रही हैं। दिल्ली मे तो प्रदूषण बेचारा केंद्र और राज्य की राजनीति का शिकार हो गया है ,दिल्ली प्रशासन और केंद्र शासन एक दूसरे पर पर्यावरण तथा यमुना नदी के प्रदूषण पर आरोप-प्रत्यारोप कर रहे हैं पर प्रदूषण कम करने के उपाय पर हाथ में हाथ धरे बैठे हैं ।अमूमन यही स्थिति अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी है।

वर्तमान में वृहद चिंतन की आवश्यकता है कि पर्यावरण संतुलन से आर्थिक, सामाजिक विकास की अवधारणा है कैसे जन्म लेंगी? उसमें गहन चिंतन विभिन्न मानव प्रजातियों के आर्थिक तथा पर्यावरण संतुलन को लेकर भी है इस विषय पर एक खुली बहस की आवश्यकता है खुली बहस इसलिए भी कि मनुष्य के जीवन के लिए जितना आवश्यक पर्यावरण संतुलन है उतना ही आवश्यक उसका आर्थिक विकास भी है अब ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ते खतरे को देखकर पर्यावरण संतुलन को आर्थिक विकास के साथ जोड़ा जाना अत्यंत महत्वपूर्ण एवं मानवीय जीवन की सुरक्षा के लिए आवश्यक है बढ़ते असमान आर्थिक विकास तथा उपभोक्तावादी प्रकृति ने जहां सामाजिक विभेद की दरार को चौड़ा कर दिया है वही विश्व स्तर पर विस्तारवाद तथा उपनिवेशवाद को बढ़ावा भी मिला है राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भेदभाव के इस बड़े स्तर को आर्थिक विकास तथा पर्यावरण संतुलन को प्राथमिकता देना नदी के दो अलग किनारों को जोड़ने जैसा ही है विकास की दौड़ में जहां मनुष्य जीवन के इस व्यस्तता में थककर वापस प्रकृति की ओर उन्मुख होना चाहता है शहरी मनुष्य प्रकृति की शीतलता, हरियाली और खुली स्वच्छंद हवा में सांस लेने के लिए उत्सुक है और कल्पना करता है कि गांव में जीवन कितना सुमधुर और स्वच्छंद आनंदमई है, इसकी दूसरी तरफ ग्रामीण जंगली इलाकों के रहने वाले लोग कल्पना करते हैं कि शहर में कितनी सुविधाएं हैं जो जीवन जीने को एकदम सरल एवं आसान बनाती है। यह द्विपक्षीय लालसा शहर में रहने वाले और ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों के बीच बराबर की है, हमें इनके आपसी संतुलन को बनाए रखना और आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संतुलन को भी बढ़ते सोपान के साथ बढ़ावा देना है यूरोपीय देशों में कई देशों ने इसके उदाहरण प्रस्तुत किये हैं, जहां आर्थिक विकास के साथ पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता दी गई है इसके लिए हमें उपभोक्तावादी संस्कृति को नियंत्रित कर नागरिकों को पर्यावरण के संतुलन के प्रति जागरूक करना होगो टेक्नोलॉजी के स्तर पर पर्यावरण अनुकूल साधनों का ऊर्जा स्रोत ग्रीन तकनीक, हरित भवन, कार्बन न्यूट्रल वाहनों की तरफ उनके नियंत्रण पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता होगी। वहीं दूसरी तरफ आदिवासियों पर ग्रामीण क्षेत्र के निवासियों को आधुनिक विज्ञान से देसी ज्ञान के साथ शिक्षित भी करने की आवश्यकता होगी पर्यावरण किसी भी परियोजना को स्थापित करने के पूर्व पर्यावरण आकलन करने की आवश्यकता है ही इसके साथ ही समाज में पड़ने वाले प्रभाव को देखने के लिए सामाजिक प्रभाव आकलन को भी मूर्त रूप देना होगो इस संतुलन को बनाने हेतु भविष्य की नीति बनाने की आवश्यकता होगी साथ ही हमको यह भी समझना होगा कि पर्वतों को मिटाने से नदियों को बांधने व जंगलों को काटने से विकास संभव नहीं है पर्यावरण संतुलन और विकास को केवल आर्थिक विकास की श्रेणी में न रखकर समग्र रूप से सामाजिक, पर्यावरणीय संस्कृति के नैतिक रूप से समझने की आवश्यकता होगी इस पर्यावरण तथा आर्थिक संतुलन को बनाए रखने के लिए हमें सर्वहारा वर्ग के हर व्यक्ति के लिए जीत सुनिश्चित करनी होगी जिसमें किसी को नुकसान ना हो एवं आम व्यक्ति पीछे ना रह जाए। यह अवधारणा यदि किसी भी समाज देश में व्याप्त होगी तभी आर्थिक विकास का पर्यावरण के साथ संतुलन स्थापित हो सकता है

इस संदर्भ में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने भी कहा है प्रकृति हमारी जरूरतों को पूरा करने के लिए है व्यक्ति की लालच को पूरा करने के लिए नहीं निर्दोष, निर्मल प्रकृति के दोहन के साथ ही मनुष्य के समाज ने अत्यधिक शोषण किया है प्रकृति के विनाश के साथ आर्थिक विकास लंबे समय तक नहीं चल सकता है यह बात जितने जल्दी मनुष्य को, देश और पूरे विश्व समुदाय को जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना ही आर्थिक तथा पर्यावरण के संतुलन के विकास के लिए शुभ संकेत होंगे आर्थिक विकास के वर्तमान संदर्भ को देखें तो यह बात बड़ी विचित्र किंतु सत्य प्रतीत होती है कि जब एक समुदाय को कुर्बान करने के लिए दूसरे समुदाय को लाभ पहुंचाया जाता है आर्थिक विकास के लिए योजनाएं कहीं बनती हैं, विस्थापित लोग कहीं और होते हैं और बिजली और अन्य सुविधाएं किसी अन्य जगह से आती है, जिसके परिणाम स्वरूप आर्थिक और पर्यावरण के संतुलन में अनेक विसंगतियां जन्म लेती हैं, और इससे सामाजिक आर्थिक संतुलन भी बिगड़ने की संभावना बलवती होती है मनुष्य की स्पृहा, कामना और लालच के सामने प्रकृति भी निष्ठ त्तर होती दिखाई दे रही है। प्रकृति के समर्पण में जो विसंगतियां और दुष्प्रभाव हमारे सामने आ रहे हैं उनमें जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, बढ़ते ओजोन छिद्र ,बढ़ता जलवायु परिवर्तन, पिघलते ग्लेशियर तथा बढ़ता समुद्री जल हम सबके लिए नई समस्याओं को जन्म देने का काम कर रहे हैं आपको ऐसा नहीं लगता कि हमारे प्रकृति विरोधी कर्मों से हमारे जीवन का अस्तित्व ही खतरे में आने लगा है इसी तरह के अनेक आसन में खतरों से निपटने के लिए आर्थिक विकास के नए मॉडलों को पर्यावरण के संतुलन के साथ जोड़ने का विकल्प हम सबके लिए एक जीवन उपयोगी मार्ग बनता नजर आ रहा है प्रकृति के असंतुलन दोहन का सर्वोत्तम उदाहरण यूरोप के विकसित देश है जिनकी पर्यावरण असंतुलन के प्रति उदासीनता की भयावह कीमत विकासशील तथा समुद्री क्षेत्रों में सीमावर्ती तथा अल्प विकसित देशों को चुकानी पड़ रही है हमें वैश्विक स्तर पर आर्थिक विकास को पर्यावरण संतुलन बनाने की दिशा में सामूहिक रूप से कारगर उपाय खोज कर संपूर्ण विश्व को ग्लोबल वार्मिंग और इसके गहरे परिणामों से सुरक्षित रखना होगा, विशेषकर उन अल्प विकसित एवं विकासशील राष्ट्रों को जिनकी जनसंख्या अग्रणी देशों में गिनी जाती है. पर्यावरण संतुलन तथा आर्थिक विकास के ढांचे को विकसित करने के लिए पर्याप्त आर्थिक संसाधन उपलब्ध नहीं है

संजीव ठाकुर, स्तंभकार, चिंतक, लेखक, रायपुर छत्तीसगढ़, 9009 415 415.

प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लगी प्रदर्शनी

अमेठी। स्थानीय ब्लॉक के परसावां गांव स्थित सेंटमेरीज इंग्लिश मीडियम स्कूल परिसर में प्रधानाध्यापक बिंदु त्रिपाठी की अगुवाई में बुधवार को पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण मुक्त बनाने को लेकर प्रदर्शनी एवं संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जीजीआईसी प्रधानाचार्य डॉ. फूलकली ने किया।

डॉ. फूलकली ने कहा कि हमें पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त बनाने की दिशा में कार्य करना होगा। आज इस आधुनिकता की चकाचौंध और प्रदूषण के चलते मनुष्यों के साथ ही जीव जंतु विभिन्न बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। स्वच्छ पर्यावरण एवं

अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें प्रकृति की ओर लौटना ही होगा, तभी बेहतर जीवन संभव होगा। विशिष्ट अतिथि सेंट जोसेफ कॉलेज लखनऊ के प्रधानाचार्य ग्रैसियस जोसेफ ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के साथ ही अंधाधुंध पेड़ों का कटान, जहां पर्यावरण को असंतुलित कर रहा है, वहीं मशीनीकरण के युग में मनुष्य पर्यावरण को प्रदूषण मुक्त करने के बजाए प्रदूषण युक्त बना रहा है। जो आने वाले भविष्य के लिए खतरनाक साबित होगा। विद्यालय प्रबंधक पीजे थॉमस ने कहा कि कोविड-19 के दौरान लोगों ने स्वच्छ 3

पर्यावरण सम्मेलन में पाकिस्तान ने फैलाए हाथ, बाढ़ से तबाही के लिए दुनिया से मांगा मुआवजा

लाहौर। आर्थिक मंदहाली से जूझ रहा पाकिस्तान किसी भी वैश्विक मंच पर जाए भारत के खिलाफ जहर उगलने व भीख मांगने से नहीं चूकता। चीन दौरे पर गए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ द्वारा राष्ट्रपति शी जिनपिंग के सामने हाथ फैलाने के बाद अब पर्यावरण सम्मेलन में भाग लेने मिस्त्र पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो-जरदारी ने पाकिस्तान में आई बाढ़ के लिए मुआवजे की मांग की। उन्होंने कहा, उनके देश में अतिवृष्टि और उसके बाद बाढ़ पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के कारण आई।

पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा इस आपदा में 40 अरब डालर से ज्यादा संपत्ति का नुकसान हुआ और हजारों लोगों की जान गई। इसलिए उनके देश को संपन्न देशों की ओर से मुआवजा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा, विकासशील देशों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान से उबारने के लिए अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था बननी चाहिए। इस बीच चीन ने गरीब देशों को पर्यावरण सुधार के लिए आर्थिक और तकनीक सहायता देने की इच्छा जताई है। यह इच्छा सम्मेलन में भाग लेने आए चीन के पर्यावरण संबंधी मामलों के दूत शी झेनहुआ ने जताई। सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने ग्रीनवाशिंग को कतई बर्दाश्त न किए जाने का आह्वान किया। ग्रीनवाशिंग शब्द का इस्तेमाल कंपनियों की उस हरकत के लिए किया जाता है जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले कार्य करती हैं और बदले में पर्यावरण सुधार के लिए बड़े कार्य करने का दावा करती हैं। लेकिन जमीन पर वे उतना कुछ नहीं करती हैं। उनके दावे हवाई होते हैं। दुनिया को कार्बन मुक्त बनाने में परमाणु शक्ति बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। परमाणु ऊर्जा से पैदा होने वाली बिजली का कई देश बेहतर इस्तेमाल कर पर्यावरण की सुरक्षा का दायित्व निभा रहे हैं। इसके लिए तकनीक संपन्न राष्ट्रों को विश्व की मदद के लिए आगे आना चाहिए। लेकिन उसके लिए मजबूत सुरक्षात्मक ढांचा भी तैयार होना चाहिए। यह बात बुधवार को पर्यावरण सम्मेलन में कही गई। कहा गया कि बिजली की बढ़ती मांग के मद्देनजर पर्यावरण की सुरक्षा के लिए ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है।

एयर क्वालिटी ट्रैकर- कैथल-करनाल सहित 21 शहरों में बेहद खराब रही वायु गुणवत्ता, दिल्ली सहित 41 में रही खराब

नई दिल्ली। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा 10 नवंबर 2022 को जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि देश के 176 शहरों में से केवल 13 में हवा बेहतर रही, जबकि 38 शहरों की श्रेणी संतोषजनक, 63 में मध्यम रही। वहीं 41 शहरों में वायु गुणवत्ता का स्तर खराब दर्ज किया गया, जबकि 21 शहरों अंबाला 336, बेगूसराय 385, बेतिया 337, चंडीगढ़ 322, दरभंगा 348, गाजियाबाद 334, ग्रेटर नोएडा 348, ग्वालियर 336, कैथल 395, करनाल 369, कटिहार 323, कोटा 302, कुरुक्षेत्र 399, मंडी गोबिंदगढ़ 362, मोतिहारी 385, पानीपत 384, पूर्णिया 304, सहरसा 377, समस्तीपुर 312, सिवान 389 और सोनीपत 365 में वायु गुणवत्ता का स्तर बेहद खराब रहा।

यदि दिल्ली-एनसीआर की बात करें तो यहां की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में है। दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स 295 दर्ज किया गया है। दिल्ली के अलावा फरीदाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 292, गाजियाबाद में 334, गुरुग्राम में 237, नोएडा में 256 पर पहुंच गया है। देश के अन्य प्रमुख शहरों से जुड़े आंकड़ों को देखें तो मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 179 दर्ज किया गया, जो प्रदूषण के मध्यम स्तर को दर्शाता है। जबकि कोलकाता में यह इंडेक्स 167, चेन्नई में 58, बैंगलोर में 112, हैदराबाद में 86, जयपुर में 124 और पटना में 253 दर्ज किया गया। देश के जिन 13 शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 या उससे नीचे यानी बेहतर रहा, उनमें आइजोल 22, बागलकोट 39, चामराजनगर 40, डिंडीगुल 42, एर्नाकुलम 50, गंगटोक 35, पुदुचेरी 36, पुणे 43, रामनाथपुरम 38, शिलांग 36, शिवसागर 40, थूथुकुड़ी 37 और विजयपुरा 46 शामिल रहे।

वहीं अगरतला, आगरा, अलवर, अनंतपुर, बीदर, बिलासपुर, चेन्नई, चिक्कामगलुरु, कोयंबटूर, गया, गुवाहाटी, हल्दिया, हसन, होसुर, हैदराबाद, इंफाल, कांचीपुरम, कन्नूर, कोल्लम, कोप्पल, मदिकेरी, मैहर, मंडीखेड़ा, मैसूर, नारनौल, ऊटी, पलवल, रामनगर, सागर, सतना, शिवमोगा, श्रीनगर, तिरुवनंतपुरम, उडुपी, वाराणसी, वृंदावन, यादगिर, और वेल्लोर आदि 38 शहरों में हवा की गुणवत्ता संतोषजनक रही, जहां सूचकांक 51 से 100 के बीच दर्ज किया गया। देश में वायु प्रदूषण के स्तर और वायु गुणवत्ता की स्थिति को आप इस सूचकांक से समझ सकते हैं जिसके अनुसार यदि हवा साफ है तो उसे इंडेक्स में 0 से 50 के बीच दर्शाया जाता है। इसके बाद वायु गुणवत्ता के संतोषजनक होने की स्थिति तब होती है जब सूचकांक 51 से 100 के बीच होती है। इसी तरह 101-200 का मतलब है कि वायु प्रदूषण का स्तर माध्यम श्रेणी का है, जबकि 201 से 300 की बीच की स्थिति वायु गुणवत्ता की खराब स्थिति को दर्शाती है। वहीं यदि सूचकांक 301 से 400 के बीच दर्ज किया जाता है जैसा दिल्ली में अक्सर होता है तो वायु गुणवत्ता को बेहद खराब की श्रेणी में रखा जाता है। यह वो स्थिति है जब वायु प्रदूषण का यह स्तर स्वास्थ्य को गंभीर और लम्बे समय के लिए नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद 401 से 500 की केटेगरी आती है जिसमें वायु गुणवत्ता की स्थिति गंभीर बन जाती है। ऐसी स्थिति होने पर वायु गुणवत्ता इतनी खराब हो जाती है कि वो स्वस्थ इंसान को भी नुकसान पहुंचा सकती है, जबकि पहले से ही बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए तो यह जानलेवा हो सकती है।

'पर्यावरण के नाम पर लिए 1500 करोड़, खर्च किए 300 करोड़'

नई दिल्ली।भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने दिल्ली में एनवायरमेंट टैक्स में घोटाले का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी (क्क) और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बड़ा हमला किया है. पार्टी की ओर से दावा किया गया है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार ने बीते सात साल में एनवायरमेंट टैक्स के नाम पर करीब 1500 करोड़ रुपये की वसूली की है, लेकिन इस अवधि में खर्चा महज 300 करोड़ रुपये ही किया है. यह खर्च भी सही जगह पर और सही तरीके से नहीं किया गया है. पार्टी का आरोप है कि एनवायरमेंट टैक्सा का इस्तेमाल पर्यावरण से जुड़े किसी प्रोजेक्ट में नहीं हुआ है, बल्कि दिल्ली सरकार ने इसे अन्य काम के लिए खर्च किया है.

दिल्ली में बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमलावर है. विभिन्न मुद्दों को लेकर आए दिन बीजेपी नेता कपिल मिश्रा और सांसद मनोज तिवारी मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमले करते रहते हैं. यह हमले दिल्ली में एमसीडी चुनाव की घोषणा के बाद और बढ़ गए हैं. इसी क्रम में बीजेपी ने एनवायरमेंट टैक्स में घोटाले का आरोप लगाकर मामला गर्म करने की कोशिश की है. पार्टी ने दावा किया है कि एक तरफ दिल्ली के लोग प्रदूषण से परेशान हैं, लोगों की सांसे अटकी हुई हैं, वहीं अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी की सरकार ने इसमें भी घोटाला कर दिया. पार्टी ने इसकी जांच कराने की मांग की है.

दूसरे मदों में खर्च हो गया 300 करोड़

बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि एनवायरमेंट टैक्स के नाम पर आम आदमी पार्टी की सरकार ने करीब 1500 करोड़ की वसूली की है. लेकिन पर्यावरण संरक्षण की दिशा में यह राशि खर्च नहीं की गई है. पार्टी की ओर से जारी प्रेसनोट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल ने पर्यावरण संरक्षण के लिए 300 करोड़ रुपये खर्च करने का दावा तो किया है, लेकिन उन्होंने यह रकम जहां जहां खर्च की है, उनमें से कोई भी प्रोजेक्ट पर्यावरण से संबंधित नहीं है.

जलवायु वित्तपोषण को अधिक पारदर्शी बनाने की जरूरत

पेरिस 2015 में पेरिस में आयोजित 21वें विश्व जलवायु सम्मेलन (कॉप 21) में, सभी देश पहली बार ग्रीनहाउस गैसों को कम करने के लक्ष्यों के साथ जलवायु परिवर्तन को सीमित करने पर सहमत हुए थे। इससे पहले, केवल विकसित देशों को ग्रीनहाउस गैसों को कम करना पड़ता था, जबकि चीन, भारत और दक्षिण कोरिया जैसे देश ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं थे।

विकासशील और उभरते देशों को अपने स्वयं के कम करने के लक्ष्य निर्धारित करने हेतु मनाने के लिए, औद्योगिक देशों ने 2015 से पहले ही उदार और निरंतर वित्तीय संसाधनों का वादा किया था। जलवायु संरक्षण और अनुकूलन के लिए समर्थन 2020 से सालाना 100 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंचना था। यह एक केंद्रीय वादा था जिसने पेरिस जलवायु समझौते को संभव बनाया। मिस्र में 27वें विश्व जलवायु सम्मेलन (कॉप 27) में जलवायु वित्त एक बार फिर एक प्रमुख विषय है। बात यह है कि धन अभी तक उस तरह प्रदान नहीं किया गया है जैसा कि वादा किया गया था, इसने पहले से ही सम्मेलन के लिए एक तनावपूर्ण माहौल पैदा कर दिया है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (ओईसीडी) के अनुसार, 2020 में अब तक का अधिकतम स्तर 82 करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया था। सिविल सोसाइटी पिछले कुछ समय से इस बात की आलोचना कर रही है कि दाता देशों द्वारा बताए गए भुगतान लक्ष्य से पीछे हैं। इस बीच यह स्पष्ट हो गया है कि वास्तविकता और वादे कितने अलग-अलग होते हैं।

वित्तपोषण में भारी अंतर- यह अहम बात है कि अंतरराष्ट्रीय जलवायु वित्तपोषण को विश्वसनीय रूप से रिकॉर्ड करना महंगा और कठिन है। पहली बात यह आती है कि यह स्पष्ट रूप से परिभाषित नहीं है। दूसरे में, दाता देश यह निर्धारित करते हैं कि वे जलवायु से संबंधित परियोजनाओं के रूप में किसे चुनते हैं।

नेचर क्लाइमेट चेंज में हाल ही में प्रकाशित एक अध्ययन में, ईटीएच ज्यूरिख और सेंट गैलेन विश्वविद्यालय के दो सहयोगियों ने पिछले 20 वर्षों की रिपोर्ट किए गए जलवायु वित्त प्रवाह पर करीब से नजर डाली है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करते हुए, उन्होंने उनके विवरणों के आधार पर 27 लाख द्विपक्षीय विकास परियोजनाओं का विश्लेषण किया और उन्हें उनकी जलवायु प्रासंगिकता के अनुसार वर्गीकृत किया। पेरिस के बाद की अवधि (2016-2019) के लिए, हमने दाताओं द्वारा आधिकारिक तौर पर जानकारी दिए जाने की तुलना में हमें लगभग 40 प्रतिशत कम जलवायु वित्तपोषण (कोष) का पता चला। जिससे यह यह निष्कर्ष निकलता है कि दाता देश न केवल वादे से कम भुगतान कर रहे हैं, बल्कि वे उन परियोजनाओं की पहचान कर रहे हैं जिनका जलवायु से बहुत कम लेना-देना है। इसके विपरीत स्पष्ट जलवायु प्रासंगिकता वाली परियोजनाओं की गणना नहीं की जाती है। सम्मेलन के लिए अधूरे वादों की प्रवृत्ति उन देशों के लिए समस्याग्रस्त है जो इस समर्थन पर निर्भर हैं, क्योंकि मामले के बारे में संदेह सीधे बातचीत को प्रभावित करता है। क्या कॉप 27 इतिहास में किए गए वादे कार्यान्वयन सम्मेलन इस बात पर निर्भर करता है कि क्या देश एक महत्वाकांक्षी वित्तपोषण एजेंडे पर सहमत हो सकते हैं। हालांकि, अब पुराने वादों से कहीं अधिक दांव पर लगा है। 100 अरब डॉलर के लक्ष्य को पूरा करना- विश्वास होने पर ही सहयोग सफल हो सकता है। विकसित देशों को यह दिखाना होगा कि वे अपने वादों को निभाने के लिए तैयार हैं। इसके लिए आवश्यक है कि वे अभी तक का गायब धन प्रदान करें और एक सामान्य समझ और विश्वास सुनिश्चित करें।

CoP-27-केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने किया इंडिया पवेलियन का उद्घाटन, जलवायु परिवर्तन को लेकर कही यह बात

सार केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने रविवार को मिस्र के शर्म अल-शेख में आयोजित कॉप-27 में इंडिया पवेलियन का उद्घाटन किया। प्रेस को जारी विपप्ति के अनुसार, कॉप-27 सम्मेलन 6 से 18 नवंबर तक के लिए निर्धारित है।

इंडिया पवेलियन में सभी देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत करते हुए यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जटिल जलवायु परिवर्तन की समस्या का सरल समाधान प्रदान किया है। उन्होंने कहा कि भारत का मानना है कि जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए कार्रवाई जमीनी स्तर से शुरू होती है, इसलिए उन्होंने %लाइफ% की थीम के साथ इंडिया पवेलियन को डिजाइन किया। इस अवसर पर जलवायु परिवर्तन को रोकने की दिशा में काम करने वाले भारत के स्कॉलर्स को सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री ने कहा, मुझे भरोसा है कि कॉप-27 की अवधि के दौरान इंडिया पवेलियन प्रतिनिधियों को याद दिलाता रहेगा कि सरल जीवन शैली और वे व्यक्तिगत प्रथाएं जो प्रकृति में टिकाऊ हैं, धरती मां की रक्षा करने में मदद कर सकती है।

यादव ने आगे कहा, भारत जलवायु वित्त से संबंधित चर्चाओं में प्रगति की उम्मीद करता है। हम नई प्रौद्योगिकियों की शुरुआत और प्रौद्योगिकियी हस्तांतरण की सुविधा के लिए नए सहयोग की भी आशा करते हैं। उन्होंने आगे कहा, मिशन लाइफ इस धरती की सुरक्षा के लिए लोगों की शक्तियों को जोड़ता है और उन्हें इसका बेहतर तरीके इस्तेमाल करना सिखाता है। यह मिशन जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई को लोकतांत्रिक बनाता है, जिसमें हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार योगदान दे सकता है। मिशन लाइफ का मानना है कि छोटे-छोटे प्रयासोंका भी बहुत बड़ा प्रभाव हो सकता है। मिस्र के समुद्र तटीय शहर शर्म अल-शेख में जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए चर्चा के वास्ते दुनियाभर से प्रतिनिधि रविवार को एकत्र हुए। यह बैठक ऐसे समय हो रही है, जब दुनिया कई अन्य संकटों से जूझ रही है। इनमें यूक्रेन युद्ध, महंगाई, भोजन और उर्जा शामिल हैं।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक सोनल मेहता केलिए प्रतीक्षा ग्राफिक्स, 127 देवी अहिल्या मार्ग, इंदौर (म.प्र.) से मुद्रित एवं 209-बी शहनाई रेसीडेंसी-2 कनाड़िया रोड इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक: डॉ. सोनल मेहता फोन : 0731-2595008 Mail.sonal12mehta@yahoo.co.in 9755040008